

Title: Demand to look into the grievances of the agitating Public Health Workers of the country.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री श्री राज नारायण जी ने 1000 की आबादी पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक रखने का फैसला किया था और ये जो जन स्वास्थ्य रक्षक रखे गये थे, वे एक हजार की आबादी पर रखे गये थे। 23 साल पहले पचास रुपये के मानदेय पर उन्हें रखा गया था लेकिन आज 23 साल बाद भी उनको पचास रुपया मानदेय दिया जा रहा है। 1997 में सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी और इस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई और सरकार ने इन स्वास्थ्य रक्षकों को यह कहा था कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, उसे आप विदड़ों कर लीजिए, सरकार आपके साथ इंसाफ करेगी। सरकार की बात मानकर जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन ने वह मुकदमा भी वापस ले लिया लेकिन अब सरकार यह कहती है कि मामला कानून मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है। यह इन लोगों के साथ मजाक है क्योंकि आज की परिस्थिति में पचास रुपया प्रतिमाह का मानदेय किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है और 23 साल बाद भी इस पचास रुपया मानदेय के संबंध में सरकार अविलम्ब निर्णय करके उन लोगो को विश्वास में ले ताकि उन लोगों को न्याय मिले। 14 तारीख को जंतर मंतर पर इन जन स्वास्थ्य रक्षकों ने प्रदर्शन किया था और निर्माण भवन में ये जन स्वास्थ्य रक्षक बड़ी संख्या में अभी तक वहां पड़े हुए हैं। भारत सरकार इसको गंभीरता से ले और इनका मानदेय तत्काल बढ़ाया जाये।